

यूक्रेन के विद्रोही इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता

प्रलिम्सि के लियै:

यूक्रेन और उसके पड़ोसी, यूक्रेन संकट, रूस, डोनेट्स्क (Donetsk), लुहान्स्क (Luhansk), मन्सिक (Minsk) समझौते, ओएससीई (OSCE), नाटो ।

मेन्स के लिये:

द्वपिक्षीय समूह और समझौते, भारत के हित पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, यूक्रेन संकट तथा इसके भू-राजनीतिक प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस दवारा यूक्रेन पर हमले की आशंका से उत्पन्न तनाव को समाप्त करने के लिये पश्चिम देशों की <mark>ओर से</mark> किये <mark>गए</mark> आह्वान के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों- **डोनेट्स्क और लुहान्स्क** को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी है।

- इसने उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया, यह पश्चिम <mark>को एक सीधी</mark> चुनौत<mark>ी है जो</mark> यह आशंका पैदा करता है कि रूस यूक्रेन पर आकरमण कर सकता है।
- पिछले कुछ हफ्तों में तनाव चरम पर है क्योंकि रूस ने शीत युद्ध के बाद से सबसे खराब संकटों में से एक के रूप में यूक्रेन की सीमाओं पर 1,50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है।
- इस घोषणा ने मिन्स्क में हस्ताक्षरित वर्ष 2015 के शांति समझौते को तोड़ दिया, जिसमें यूक्रेनी अधिकारियों को विद्रोही क्षेत्रों में व्यापक स्व-शासन की पेशकश करने की आवश्यकता थी।

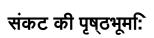
रूस का रुख:

- इसने मौज़ूदा संकट के लिय उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को जिम्मेदार ठहराया और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को रूस के लिये
 एक संभावित खतरा बताया।
- आरोप लगाया कि यूक्रेन को रूस की ऐतिहासिक भूमि विरिक्ति में मिली थी और सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिम द्वारा रूस को शामिल करने के लिये इसतेमाल किया गया था।
- 🛮 वह चाहता है कि पश्चिमी देश यह गारंटी दें कि नाटो यूक्रेन <mark>और अन्य</mark> पूर्व सोवयित देशों को सदस्य के रूप में शामलि होने की अनुमति नहीं देगा।
- इसने गठबंधन से यूक्रेन में हथियारों की तैनाती रोकने और पूर्वी यूरोप से अपनी सेना वापस लेने की भी मांग की है।
 - पश्चिमी देशों ने इस मांग को खारिज कर दिया है।

Ganging up at Ukraine's border

NATO is planning to establish four new multinational battlegroups - totalling 4,000 troops - in Romania, Bulgaria, Hungary and Slovakia, in response to Russia's military build-up around Ukraine





- यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषायी और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं।
 - रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिये देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जाता है।

The Vision

- सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण था।
- पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र (डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र) वर्ष 2014 से रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है।
 यह आंदोलन क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप (Crimean Peninsula) पर कब्ज़ा कर लिया गया।
- अप्रैल माह में रूस समर्थक विद्रोहियों ने पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया (रूस ने उन्हें हाइब्रिड युद्ध के माध्यम से समर्थन दिया)
 और मई 2014 में, डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों में विद्रोहियों ने यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने हेतु एक जनमत संग्रह आयोजित किया।
- तब से यूकरेन के भीतर मुख्य रूप से रूसी भाषी क्षेत्रों (जहाँ 70% से अधिक लोग रूसी बोलते हैं) में विद्रोहियों और यूक्रेनी बलों के बीच गोलाबारी और संघर्ष जारी है, जिसमें लगभग 14,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, साथ ही इसके कारण लगभग 1.5 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रतिकृल प्रभाव पड़ा है।
- अक्तूबर 2021 के बाद तब से गोलाबारी काफी तेज़ हो गई है, जब रूस ने यूक्रेन के साथ सीमाओं पर सैनिकों को तैनात करना शुरू किया था।
- यदि डोनबास क्षेत्र में स्थिति बिगिड़ती है, तो युद्ध की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। युद्ध के प्रकोप को रोकने का एक तरीका यह होगा कि 'मिन्स्क समझौतों' को तुरंत लागू किया जाए, जैसा कि रूस ने सुझाव दिया है।

मनि्स्क समझौते:

- दो मिन्स्क समझौते हैं- मिन्स्क-1 और मिन्स्क-2, जिसका नाम बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नाम पर रखा गया है, जहाँ इस संबंध में वार्ता आयोजित हुई थी।
- मिन्स्क-1:
 - ॰ मिन्स्क-1 को सतिंबर 2014 में यूक्रेन त्रपिक्षीय संपर्क समूह [यानी यूक्रेन, रूस और यूरोप सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (OSCE)] द्वारा तथाकथति 'नॉरमैंडी प्रारूप' में फ्रॉंस और जर्मनी की मध्यस्थता के साथ लिखा गया था।
 - मिन्स्क-1 के तहत यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों ने 12-सूत्रीय युद्धविराम समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कैदियों का आदान-प्रदान, मानवीय सहायता और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी।
 - हालाँकि दोनों पक्षों दवारा किये गए उल्लंघन के कारण समझौता लंबे समय तक नहीं चल सका।
- मिन्स्क-2

- ॰ जैसे ही विद्रोही यूक्रेन में आगे बढ़े, फरवरी 2015 में, रूस, यूक्रेन, OSCE के प्रतिनिधियों और डोनेट्स्क एवं लुहान्स्क के नेताओं ने एक नए 13-सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसे अब मिन्स्क-2 समझौते के रूप में जाना जाता है।
- ॰ इस नए समझौते में यूक्रेनी कानून के अनुसार तत्काल युद्धवरिाम, भारी हथियारों की वापसी, OSCE निगरानी, डोनेट्स्क और लुहान्स्क हेतु अंतरमि स्वशासन पर वार्ता के प्रावधान थे।
- ॰ इसमें संसद दवारा विशेष दरजे की सवीकृति, लडाकों के लिये कषमा एवं माफी, बंधकों एवं कैदियों के आदान-परदान, मानवीय सहायता आदि से संबंधति प्रावधान भी थे।
 - हालाँक इन परावधानों को लागु नहीं किया गया है, क्योंक िलोकपरिय रूप से इस 'मनिसक' समझौते को एक 'पहेली' के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि यूक्रेन और रूस के बीच समझौते की वरिोधाभासी व्याख्याएँ हैं।

इस मुद्दे पर वभिनि्न राष्ट्रों का रुख:

- 🔳 संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही दो अलग-अलग कुषेत्रों में अमेरिकी वयक्तियों दवारा "नए नविश, वयापार, और वित्तपोषण'' पर परतिबंधों की घोषणा कर चुका है।
- 🔳 जापान के अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों में शामलि होने की संभावना है, जबकि फ्रॉंसीसी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि यूरोपीय संघ (European Union- EU) भी रूस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर चर्चा में है।
 - ॰ युरोपीय संघ ने "अंतरराषटरीय कानुन के साथ-साथ मनिसक समझौतों के घोर उललंघन" पर रूस की नदिा की है ।
- 🛮 यूनाइटेड कगिडम ने और अधिक प्रतबिंध लगाने की चेतावनी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस के कार्यों को अस्वीकार्य तथा अनुचित बताया है।

भारत का रुख:

- भारत पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निदा में शामिल नहीं हुआ और इस मुद्दे पर अपना तटस्थ रुख रखा।
- नवंबर 2020 में भारत ने संयकत राषटर (UN) में यकरेन दवारा परायोजित एक परसताव के खिलाफ मतदान करके रस का समरथन कथा, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निदा की गई थी।
- हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह भी सुझाव दिया कि "शांत और रचन<mark>ात्</mark>मक कू<mark>टनीता</mark>" समय की आवश्यकता है और तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहयै। Vision
 - ॰ रूस ने भारत के रुख का स्वागत किया है।

आगे की राह

- स्थिति का एक व्यावहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रिक्रिया को पुनर्जीवित करना है, अत: पश्चिम (अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों) को दोनों पक्षों से बातचीत फरि से शुरू करने और सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने हेतु मिन्स्क <mark>शांति सि</mark>मझौते (Minsk Peace Process) के अनुसार अपनी प्रतबिद्धताओं को पूरा करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।
- व्यवहार में मिन्सक समझौता आदरश स्थिति से काफी दूर की बात है। यह एक आधार रेखा हो सकती है जिससे मौजूदा संकट का एक राजनयिक समाधान खोजा जा सकता है तथा इसे पुनरजीवति करना 'एकमात्र मार्ग हो सकता है जसिका पालन करके शांति को स्थापति कया जा सकता है' जैसा क फिरॉंसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा है।
- 🛮 यूक्रेन के लिये यह अपनी सीमाओं पर नियंत्रण हासलि करने तथा रूसी आक्रमण के खतरे को प्रतिसंतुलति करने में मदद कर सकता है, जबकि रूस के लिये यह सुनिश्चिति करने का एक तरीका हो सकता है कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा न बने और यह सुनिश्चित करे कि रूसी भाषा व संस्कृति यूक्रेन में एक नए संघीय संवधान के तहत संरक्षति हैं।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/russia-recognises-rebel-regions-of-ukraine-as-independent